

UP ने नए विश्वविद्यालयों और रोज़गारों को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने [शिक्षा](#) की गुणवत्ता में सुधार और [रोज़गार](#) के अवसरों को बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण नीतियों एवं पहलों को स्वीकृति दी है।

मुख्य बिंदु

- नीतिअनुमोदन:
 - शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये कैबिनेट द्वारा 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' को मंजूरी दी गई।
 - इसमें नमिन्लखित प्रावधान शामिल हैं:
 - स्टाम्प ड्यूटी में छूट
 - पूंजीगत सब्सिडी
 - प्रायोजक निकायों के लिये विशेष प्रोत्साहन
 - शीर्ष 50 रैंक वाले विश्वविद्यालयों के लिये अतिरिक्त लाभ
- नये नज़ी विश्वविद्यालयों की स्थापना:
 - दो नये नज़ी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई:
 - राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा में के.डी. विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
 - वदिया बाल मंडली द्वारा मेरठ में 42.755 एकड़ परिसर में वदिया विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- उच्च शिक्षा पर प्रभाव:
 - इसका उद्देश्य स्थानीय उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूर्ण करने के लिये नज़ी नविश को बढ़ाना है।
 - उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है।
 - इससे युवाओं के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार के अवसर उत्पन्न होने की आशा है।
- स्वरोज़गार योजना:
 - स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये नई योजना शुरू की गई:
 - सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिये 5 लाख रूपए तक के ऋण पर सब्सिडी।
 - 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य।
 - प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को सहायता।
 - पात्रता और फोकस/केंद्र:
 - आवेदकों के लिये आवश्यक है कि उन्होंने कम से कम आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की हो।
 - इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा वालों को प्राथमिकता।
 - इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में [रोज़गार को बढ़ावा](#) देना है।